[2015] 10 एस. सी. आर. 85

यूनियन ऑफ इंडिया

बनाम

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11396/2015)

22 सितंबर, 2015

[ए. के. सिकरी और आर. एफ. नरीमन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-भाग I, धारा 14-भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान-अधिनियम के भाग I को लागू करना-उत्पाद साझाकरण अनुबंध (पी. एस. सी.)-भारत संघ और कंपनियों के बीच ताप्ती और पन्ना मुक्त तेल और गैस क्षेत्रों के लिए निष्पादन-पक्षों के बीच विवाद-मध्यस्थता खंड का आह्वान और मध्यस्थ की नियुक्ति-पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता कि मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होगा और मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन है-पी. एस. सी. के तहत कुछ विवाद-यू. ओ. आई. द्वारा लंदन में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत-मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आंशिक पुरस्कार-मध्यस्थता को अलग करने के लिए यू. ओ. आई. द्वारा धारा 34 के तहत दायर याचिका।

अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम का भाग I लागू नहीं था और इसे अनिवार्य रूप से मध्यस्थता समझौते के साथ पूरी तरह से असंगत होने के कारण बाहर रखा गया था-इसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने धारा 14 के तहत लंबित अपील को विचारणीय नहीं के रूप में खारिज कर दिया-समीक्षा याचिका के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी गई-एसएलपी में, कहा गयाः मध्यस्थता समझौते भारत एल्यूमीनियम कंपनी के फैसले से पहले होने के कारण, भाटिया इंटरनेशनल द्वारा शासित होंगे, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भाग-I लागू नहीं होगा यदि इसे आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है, तो मध्यस्थता का न्यायिक स्थान भारत के बाहर है या मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून के अलावा एक अन्य कानून है-तत्काल मामले में, इस अदालत ने पहले ही निर्धारित कर दिया था, तत्काल मामले में, इस न्यायालय ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन में है और मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा नियंत्रित होता है, इस प्रकार, यू. ओ. आई. के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं था कि भाग-I लागू होगा-उसी भाग्य के साथ मिलने के लिए, उसी आधार पर समीक्षा याचिका और उपचारात्मक याचिका को खारिज करके दो बार सुलझाए गए प्रश्न को फिर से खोलने का बहादुर प्रयास-याचिका के संबंध में

कि न्यायपालिका अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों से नहीं जुड़ेगी, पी. एस. सी. के खंड का प्रभाव तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न नहीं उठाता है और तथ्यों से असंबंधित अधिकार क्षेत्र का शुद्ध प्रश्न नहीं है-इस प्रकार, दोनों न्यायपालिका के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर, धारा के तहत आवेदन, धारा 14 के तहत आवेदन खारिज किया जाना-यह न्यायालय की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है क्योंकि केवल UNCITRAL मध्यस्थता नियमों के तहत आगे बढ़ने और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय से प्रतिकूल निर्णय प्राप्त करने के बाद ही आवेदन धारा 14 के तहत दायर किया गया था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ 2014 (6) एस. सी. आर. 456: (2014) 7 एस. सी. सी. 603; भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस. ए. और एक अन्य 2002 (2) एस. सी. आर. 411: (2002) 4 एस. सी. सी. 105; नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बनाम सिंगर कंपनी 1992 (3) एस. सी. आर. 106: (1992) 3 एस. सी. सी. 551; वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड और एक अन्य 2008 (1) एस. सी. आर. 501: (2008) 4 एस. सी. सी. 190; भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज, इंक. (2012) 9 एस. सी. सी.;

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य 2011 (8) एस. सी. आर. जीजीभॉय 1970 (3) एस. सी. आर. 830: (1970) 1 एस. सी. सी. 613-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2014 (6) एस. सी. आर. 456 संदर्भित पैरा 1

2002 (2) एस. सी. आर. 411 संदर्भित पैरा 7

1992 (3) एस. सी. आर. 106 संदर्भित पैरा 10

2008 (1) एस. सी. आर. 501 संदर्भित पैरा 14

(2012) 9 एस. सी. सी. संदर्भित पैरा 15

2011 (8) एस. सी. आर. 569 संदर्भित पैरा 17

2010 (12) एस. सी. आर. 259 संदर्भित पैरा 17

2011 (14) एस. सी. आर. 301 संदर्भित पैरा 17

2015 एस. सी. आर. 697 संदर्भित पैरा 17

970 (3) एस. सी. आर. 830 संदर्भित पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेष अनुमति याचिका संख्या 11396/2015

2013 के ओ. एम. पी. संख्या 671 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 03.07.2014 के निर्णय और आदेश से।

रंजीत कुमार, एस. जी., तुषार मेहता, ए. एस. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्याम दीवान, इन्दु मल्होत्रा, समीर पारेख, सोनाई बसु पारेख, ललित चौहान, अमित भंडारी, अभिनय, अभिषेक विनोद देशमुख, एस. लक्ष्मी अय्यर, उदयादित्य, पारेख एंड कंपनी, अभिजीत सिन्हा, संगीता मंडल, स्वाति सिन्हा, देबेश पांडा, विजय कुमार, शांतनु बंसल, फॉक्स मंडल और कंपनी, सुनील के जैन, पवनश्री अग्रवाल, कौशिक चौधरी, सुनील कुमार जैन उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था-

बी. आर. एफ. नरीमन, जे.

1 वर्तमान मामला 28 मई, 2014 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ, (2014) 7 एस. सी. सी. 603 में दिए गए इस न्यायालय के फैसले की अगली कड़ी के रूप में सामने आता है।

2. 28 मई, 2014 को इस न्यायालय के फैसले का कारण बनने वाले तथ्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत

संघ, एनरॉन ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड और ओ. एन. जी. सी. के बीच ताप्ती और पन्ना मुक्त क्षेत्रों के लिए दो उत्पादन साझाकरण अनुबंध (इसके बाद "पी. एस. सी". के रूप में संदर्भित) निष्पादित किए गए। पी. एस. सी. के प्रासंगिक खंड जहां तक वे वर्तमान विवाद पर लागू होते हैं, वे इस प्रकार हैंः -

"अनुच्छेद 32: लागू करने योग्य कानून और अनुबंध की भाषा।

32.1 अनुच्छेद 33.12 के प्रावधानों के अधीन, इस अनुबंध को भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या की जाएगी।

32. 2 इस अनुबंध में कुछ भी सरकार या ठेकेदार को इस अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करने का अधिकार नहीं देगा जो भारत के कानूनों का उल्लंघन करेगा।

अनुच्छेद 33: एकल अनुभव, समन्वय और मध्यस्थता

33.9 मध्यस्थता कार्यवाही 1985 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के मध्यस्थता नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी, सिवाय इसके कि

इन नियमों और इस अनुच्छेद 33 के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, इस अनुच्छेद 33 के प्रावधानों को नियंत्रित किया जाएगा।

33.12 इस अनुच्छेद के अनुसार सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान, जब तक कि पार्टियां अन्यथा सहमत न हों, लंदन, इंग्लैंड होगा और अंग्रेजी भाषा में संचालित किया जाएगा। इस अनुच्छेद 33 में निहित मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा। जहां तक संभव हो, पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत और किसी भी लंबित दावे या विवाद के बावजूद इस अनुबंध की शर्तों को लागू करना जारी रखेंगे।

34.2 इस अनुबंध को किसी भी मामले में संशोधित, संशोधित, विविध या पूरक नहीं किया जाएगा, सिवाय सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज के, जिसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जिस पर संशोधन या संशोधन प्रभावी होगा।"

3. उल्लेखनीय है कि एनरॉन ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। 24. 2.2004 और 10.1.2005 के दो संशोधन समझौतों द्वारा एनरॉन

ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड को बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए पीएससी में संशोधन किया गया था। चूंकि 2010 में किसी समय भारत संघ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड के बीच कुछ विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए थे, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड ने मध्यस्थता खंड को लागू किया और श्री पीटर लीवर, क्यूसी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। भारत संघ ने न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी को मध्यस्थ नियुक्त किया और श्री क्रिस्टोफर लॉ एस. सी. को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 14.9.2011 को, भारत संघ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड ने मध्यस्थता के स्थान को लंदन, इंग्लैंड में बदलने पर सहमति व्यक्त की और इस आशय के पक्षों द्वारा एक अंतिम आंशिक सहमति पुरस्कार दिया गया और विधिवत हस्ताक्षर किए गए। 12.9.2012 को, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक अंतिम आंशिक निर्णय पारित किया जो भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर 13.12.2012 की धारा 34 याचिका का विषय बन गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22-3-2013 के एक निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लिया कि धारा 34 के तहत दायर की गई उक्त याचिका विचारणीय है। इस न्यायालय ने दिनांक 28.5.2014 के एक विस्तृत फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय को उलट दिया। चूंकि यह निर्णय

प्रभावी रूप से वर्तमान एसएलपी में उठाए गए विवाद को निर्धारित करता है, इसलिए इसे कुछ विस्तार से निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को बताने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

"इससे पहले कि हम दोनों पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों का विश्लेषण करें, विभिन्न तथ्यात्मक और कानूनी बिंदुओं पर ध्यान देना उचित होगा जिन पर पक्षकार सहमत हैं। यहाँ विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] में घोषित कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। पक्षकार सहमत हैं और दिनांक 14-9-2011 के अंतिम आंशिक सहमति पुरस्कार से यह भी स्पष्ट है कि दावेदारों की दिनांक 16-12-2010 की मध्यस्थता सूचना के तहत शुरू किए गए मध्यस्थता के उद्देश्यों के लिए मध्यस्थता का न्यायिक स्थान (या कानूनी स्थान) लंदन, इंग्लैंड होगा। पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थता की सूचना की सुनवाई पेरिस, फ्रांस, सिंगापुर या किसी अन्य स्थान पर हो सकती है जिसे न्यायाधिकरण सुविधाजनक मानता है। पक्षों द्वारा यह भी सहमति व्यक्त की गई है कि पी. एस. सी. के अनुच्छेद 33 में मध्यस्थता समझौते के नियम और शर्तें पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे और मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

पक्षों के बीच आवश्यक विवाद यह है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I मध्यस्थता समझौते पर लागू होगा, इस

तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर है। इस मुद्दे का एक निर्णायक उत्तर खोजने के लिए कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग । की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है, पक्षों के इरादे का पता लगाना आवश्यक होगा। इसके अलावा पक्ष किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं हैं।

हमारी यह भी राय है कि चूंकि बाल्को [बाल्को बनाम कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी सेवा निगम, (2012) 9 एस. सी. सी. 552: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 810] में निर्धारित कानून के अनुपात को संविधान पीठ द्वारा ही संभावित रूप से लागू किया गया है, इसलिए हम भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] में दिए गए निर्णय से बाध्य हैं। इसलिए, शुरुआत में, भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] के प्रासंगिक अनुपात को पैरा 32 में पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो इस प्रकार हैः (एस. सी. सी. पी. 123)

"32. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम मानते हैं कि भाग । के प्रावधान सभी मध्यस्थताओं और उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे। जहाँ ऐसा मध्यस्थता भारत में आयोजित किया जाता है, वहाँ भाग । के प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगे और पक्षकार केवल भाग । के अपमानजनक प्रावधानों द्वारा अनुमत सीमा तक विचलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के

मामलों में भाग I के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक कि पक्षकार समझौते द्वारा, व्यक्त या निहित, इसके सभी या किसी भी प्रावधान को बाहर नहीं करते हैं। उस स्थिति में पक्षों द्वारा चुने गए कानून या नियम प्रबल होंगे। भाग I में कोई भी प्रावधान, जो उस कानून या नियमों के विपरीत या बहिष्कृत है, लागू नहीं होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पी. एस. सी. के प्रासंगिक अनुच्छेदों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा, ताकि पक्षों के वास्तविक इरादे का पता लगाया जा सके कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को बाहर रखा गया है। यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32.1 और 32.2 लागू कानून और अनुबंध की भाषा से संबंधित हैं जैसा कि लेख के शीर्षक से स्पष्ट है जो "लागू कानून और अनुबंध की भाषा" है। अनुच्छेद 32.1 अनुबंध के उचित कानून यानी भारत के कानूनों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32.2 एक घोषणा करता है कि अनुबंध में निहित प्रावधानों में से कोई भी सरकार या ठेकेदार को अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करने का अधिकार नहीं देगा जो भारत के कानूनों का उल्लंघन करेगा।

अनुच्छेद 33 मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के संबंध में एक बहुत ही विस्तृत प्रावधान करता है। दोनों अनुच्छेद परस्पर मेल नहीं खाते हैं-एक (अनुच्छेद 32) अनुबंध के उचित कानून से संबंधित है,

दूसरा (अनुच्छेद 33) ए. डी. आर. से संबंधित है अर्थात पक्षों के बीच परामर्श; सुलह; एकमात्र विशेषज्ञ का संदर्भ और अंततः मध्यस्थता। अनुच्छेद 33 के तहत, सबसे पहले पक्षों द्वारा आपस में विवादों को निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 33.1)। यदि ये प्रयास विफल हो जाते हैं, तो पक्षकार समझौते द्वारा विवाद को एकमात्र विशेषज्ञ के पास भेजेंगे (अनुच्छेद 33.2)। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में प्रावधान यह प्रदान करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ होंगे (अनुच्छेद 33.4)। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। यदि अनुच्छेद 33.4 के तहत प्रक्रिया विफल हो जाती है, तो पीड़ित पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय से संपर्क कर सकता है (अनुच्छेद 33.5)। इसके अलावा, यदि दोनों मध्यस्थ दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहते हैं, तो हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का महासचिव किसी भी पक्ष के अनुरोध पर तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है। इसके बावजूद, भारत के प्रत्यर्थी संघ के इस कथन की सराहना करना मुश्किल है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (भाग I) मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। यदि भारत संघ यह सुनिश्चित करने का इरादा रखता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा, तो अनुच्छेद 33.5

में यह प्रावधान होना चाहिए था कि अपने मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाले पक्षकार की चूक में, ऐसा मध्यस्थ, प्रथम पक्षकार के अनुरोध पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार, किसी भी पक्ष द्वारा चूक के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। यह, हमारी राय में, एक मजबूत संकेत है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की प्रयोज्यता को पक्षों द्वारा सर्वसम्मति से बाहर रखा गया था। इसके अलावा, मध्यस्थता कार्यवाही यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल. नियम, 1976 (अनुच्छेद 33.9) के अनुसार संचालित की जानी है। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि इस अनुबंध के तहत विवादों और दावों को मध्यस्थता करने का अधिकार इस अनुबंध की समाप्ति (अनुच्छेद 33.10) से बच जाएगा।

वह अनुच्छेद जो यहाँ विवाद का आधार प्रदान करता है वह अनुच्छेद 33.12 है जो प्रदान करता है कि मध्यस्थता का स्थान लंदन होगा और मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा। ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि पहले देखा गया है, कि अंतिम आंशिक सहमति पुरस्कार द्वारा, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि दावेदारों के दिनांक 16-12-2010 के मध्यस्थता नोटिस के तहत शुरू किए गए मध्यस्थता के उद्देश्यों के

लिए न्यायिक स्थान (या मध्यस्थता का कानूनी स्थान) लंदन, इंग्लैंड होगा।

पी. एस. सी. के उपरोक्त अनुच्छेदों को सार्थक रूप से पढ़ने पर हमारी राय है कि अनुबंध का उचित कानून भारतीय कानून है; मध्यस्थता समझौते का उचित कानून इंग्लैंड का कानून है। इसलिए, क्या यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं किया गया है? [पैरा 36-42 पर]

4. न्यायालय ने पैराग्राफ 45 में कहा कि यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि मध्यस्थता का स्थान एक अनन्य क्षेत्राधिकार खंड के अनुरूप नहीं है और फिर निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः -

"हमारी राय में, सुलामेरिका मामले में ये टिप्पणियां [(2013) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 102:12 ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 638:12 डब्ल्यू. एल. 14764] इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष से ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी जहाँ पक्ष अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच भागते रहेंगे। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (भारतीय) के भाग I के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है; जो मध्यस्थता समझौते के साथ पूरी तरह से असंगत है जो प्रदान करता है कि मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होगा। इस प्रकार प्रत्यर्थी

के लिए मध्यस्थता कार्यवाही में दिए गए किसी भी निर्णय को चुनौती देने का उपाय इंग्लैंड और वेल्स के मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत होगा। इस तरह के आवेदन पर अब इंग्लैंड की अदालतों द्वारा विचार किया जाएगा या नहीं, यह हमारे लिए जांच करने के लिए गर्म है, इसकी जांच इंग्लैंड में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा की जानी चाहिए। [पैरा 57 पर]

इसने अंततः निष्कर्ष निकाला कि

"हम श्री गांगुली के इस कथन से भी सहमत नहीं हैं कि चूंकि इसमें शामिल मुद्दे भारत की सार्वजनिक नीति से संबंधित हैं, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I लागू होगा। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग I की प्रयोज्यता पुरस्कार को चुनौती देने की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। सार्वजनिक नीति के आधार पर पुरस्कार को चुनौती दी जाए या नहीं, इसे इस पूर्व शर्त को पूरा करना होगा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता समझौते पर लागू होता है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में अधिकारिता संबंधी त्रुटि की है कि अनुच्छेद 33.12 में निहित प्रावधान केवल कार्यवाही पर लागू क्यूरियल कानून के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि पक्षों ने समझौते द्वारा यह प्रावधान किया है कि मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन में होगा। पी. एस. सी. में आवश्यक संशोधन भी

किया गया है, जैसा कि अंतिम आंशिक सहमति पुरस्कार दिनांक 14-9-2011 द्वारा दर्ज किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 न्यायिक स्थान को परिभाषित या उल्लेख नहीं करता है। दूसरी ओर "न्यायिक सीट" शब्द को विशेष रूप से अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि पक्षकार समझ गए थे कि इंग्लैंड का मध्यस्थता कानून मध्यस्थता समझौते पर लागू होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हैं कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता समझौते पर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,

हम मानते हैं किः दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं है।

हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को आगे खारिज और दरकिनार करते हैं कि भले ही मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा और मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन में होगा। मध्यस्थता अधिनियम का भाग । अभी भी लागू होगा क्योंकि मूल अनुबंध को नियंत्रित करने वाले कानून भारतीय कानून हैं।

यदि प्रतिवादी के खिलाफ अंतिम निर्णय दिया जाता है, तो सार्वजनिक नीति के आधार पर भारत में इसकी प्रवर्तनीयता का विरोध किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यदि पुरस्कार को भारत के बाहर लागू करने की मांग की जाती है, तो यह भारतीय पक्ष को बिना किसी आधार के उपचार के छोड़ देगा क्योंकि पक्षों ने सहमति से यह प्रावधान किया है कि मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होगा। इसलिए, इसके खिलाफ उपाय इंग्लैंड में खोजना होगा, जहां न्यायिक सीट स्थित है। हालाँकि, हम अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि चूंकि अनुबंध को नियंत्रित करने वाली मूल कानून भारतीय कानून है, इसलिए इंग्लैंड की अदालतों को भी, यदि मध्यस्थता को चुनौती दी जाती है, तो भारतीय कानून अर्थात् सार्वजनिक नीति के सिद्धांत आदि को लागू करके इस मुद्दे का फैसला करना होगा, जैसा कि भारतीय कानून में प्रचलित है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय [(2013) 199 डी. एल. टी. 469] को खारिज कर दिया जाता है। (पेरा 74-77)

5. तथ्यों के कथन को जारी रखते हुए, वर्तमान एसएलपी दिनांकित 3.7.2014 एक निर्णय से उत्पन्न होती है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय

ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत दायर एक आवेदन को 12.6.2013 को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि इस न्यायालय का निर्णय दिनांकित 28.5.2014 ने अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग-I लागू नहीं है, धारा 14 के तहत दायर की गई ऐसी याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

6. यह और इंगित करने की आवश्यकता है कि उक्त निर्णय दिनांक 28.5.2014 के खिलाफ एक समीक्षा याचिका 31.7.2014 पर खारिज कर दी गई थी और उसके बाद दायर एक सुधारात्मक याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

7. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि दिनांकित आंशिक सहमति पुरस्कार अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि यह पी. एस. सी. के खंड 34.2 के विपरीत था जिसमें कहा गया था कि पी. एस. सी. में केवल तभी संशोधन किया जा सकता है जब सभी पक्ष लिखित समझौते द्वारा इसमें संशोधन करें। चूंकि ओ. एन. जी. सी., जो पी. एस. सी. का एक पक्ष था, ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उक्त अंतिम आंशिक सहमति अधिकार क्षेत्र के बिना था। ऐसा होने पर, मध्यस्थता का स्थान लंदन नहीं कहा जा सकता है और पी. एस. सी. का खंड 33.12 जिसने "स्थल" लंदन को शासन करना जारी रखा। चूँकि पी. एस. सी. में निहित मध्यस्थता खंड 12.9.2012 से पहले का है,

इसलिए भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस. ए. और अन्य, (2002) 4 एस. सी. सी. 105 में निर्णय शासित होगा और इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 28.5.2014 पर दिया गया निर्णय उनके रास्ते में नहीं आएगा, इसके बावजूद कि एक समीक्षा याचिका और एक उपचारात्मक याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि, उनके अनुसार, उठाया गया मुद्दा प्रकृति में अधिकार क्षेत्र होने के कारण, रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। उन्होंने अपनी प्रस्तुति को और मजबूत करने के लिए यूके मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्रावधानों को पढ़ा।

8. दूसरी ओर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी ने भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री रंजीत कुमार की दलीलों का जोरदार विरोध किया। उनके अनुसार, 28.5.2014 दिनांकित निर्णय अंतिम अंतर-पक्षीय होने के कारण दोनों पक्षों को न्यायिक आधार पर और एक उदाहरण के रूप में बाध्य करता है। उनके अनुसार, निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले के तथ्यों पर मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग-1 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। उन्होंने आगे यह प्रदर्शित किया कि भारत संघ ने पहले ही धारा 14 के तहत मांगे गए उपाय का लाभ उठाया था और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय दिनांक 1 का निर्णय आमंत्रित किया

था, जिसके द्वारा मध्यस्थ के रूप में श्री पीटर लीवर की नियुक्ति पर उसकी आपत्तियों को पहले ही खारिज कर दिया गया था।

9. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा उठाए गए तर्क को पूरी तरह से समझने के लिए, भारत में मध्यस्थता के कानून के इतिहास में तल्लीन होना आवश्यक है। 1996 के अधिनियम से पहले, तीन अधिनियम भारत में मध्यस्थता के कानून को नियंत्रित करते थे-मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937, जिसने जिनेवा कन्वेंशन को प्रभावी बनाया, मध्यस्थता अधिनियम, 1940, जो घरेलू निर्णय से संबंधित था, और विदेशी निर्णय (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961, जिसने 1958 के न्यूयॉर्क कन्वेंशन को प्रभावी बनाया और जो विदेशी निर्णय को दी गई चुनौतियों से संबंधित था।

10. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बनाम सिंगर कंपनी, (1992) 3 एस. सी. सी. 551 में, इस न्यायालय ने विदेशी निर्णय अधिनियम की धारा 9 (बी) का अर्थ लगाते हुए कहा कि जहां मध्यस्थता समझौता भारत के कानून द्वारा शासित होता है, वहां केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1940 लागू होगा, न कि विदेशी निर्णय अधिनियम। सिंगर के मामले में मध्यस्थता खंड इस प्रकार हैः

"सामान्य शर्तों के खंड 27 का उपखंड 6 एक भारतीय ठेकेदार के संबंध में मध्यस्थता से संबंधित है और उक्त खंड का उपखंड 7 एक विदेशी ठेकेदार के संबंध में मध्यस्थता से संबंधित है। बाद वाला प्रावधान कहता है:

"27. 7 विदेशी ठेकेदार की स्थिति में, मध्यस्थता तीन मध्यस्थों द्वारा संचालित की जाएगी, एक-एक को मालिक और ठेकेदार द्वारा नामित किया जाएगा और तीसरे को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, पेरिस के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। ऊपर बताए गए सभी नियमों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के सुलह और मध्यस्थता के नियम ऐसे मध्यस्थताओं पर लागू होंगे। मध्यस्थता ऐसे स्थानों पर की जाएगी जो मध्यस्थ निर्धारित करें।

"भारतीय ठेकेदार के संबंध में, खंड 27 का उपखंड 6.2 कहता है कि मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अनुसार नई दिल्ली में की जाएगी। इसमें लिखा है:

"27.6.2 मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा।

सामान्य शर्तें आगे प्रदान करती हैंः "[टी] वह अनुबंध हर तरह से भारतीय कानूनों के अनुसार समझा और शासित किया जाएगा।" (32.3)

17 अगस्त, 1982 को दोनों पक्षों द्वारा किए गए औपचारिक समझौतों में विवादों के निपटारे के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 4.1 में कहा गया हैः

> "4.1 विवादों का निपटारा-पार्टियों द्वारा और उनके बीच विशेष रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या अनुबंध के विषय-वस्तु को छूने वाले सभी मतभेद या विवाद, अनुबंध की सामान्य शर्तों के 27.6.1 और 27.6.2 को छोड़कर खंड 26 और 27 में निर्दिष्ट निपटान और मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा तय किए जाएंगे। (पैरा 4)

11. इसके बावजूद कि उस मामले में निर्णय एक विदेशी निर्णय था, इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि अनुबंध का मूल कानून भारतीय कानून था और चूंकि मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा था, इसलिए मध्यस्थता खंड भारतीय कानून द्वारा शासित होगा न कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के नियमों द्वारा। यह मामला होने के कारण, यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल यह तथ्य कि मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए आई. सी. सी. न्यायालय द्वारा चुना गया स्थान लंदन था, उस अधिनियम के संचालन

को बाहर नहीं करता है जो घरेलू निर्णय यानी 1940 के अधिनियम से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण सजा में, न्यायालय ने आगे कहाः

> "फिर भी, अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता और प्रक्रियात्मक मामलों में उस देश की कानूनों की प्रयोज्यता को सक्षम भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता और मध्यस्थता से संबंधित सभी मामलों में भारतीय कानूनों के संचालन के साथ समवर्ती और सुसंगत के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि मुख्य अनुबंध के साथ-साथ जो मध्यस्थता खंड में निहित है वह भारत के कानूनों द्वारा शासित है। (पैरा-53)

12. यह देखा जा सकता है कि सिंगर के मामले में इस न्यायालय ने अनुबंध के मूल कानून और मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले कानून के बीच के अंतर को प्रभावी नहीं बनाया। इसलिए, चूंकि विदेशी निर्णय अधिनियम की धारा 9 (बी) के निर्माण ने उपरोक्त स्थिति पैदा की और समवर्ती क्षेत्राधिकार के सिद्धांत को जन्म दिया, 1996 के अधिनियम ने निरस्त विदेशी निर्णय अधिनियम, 1961 की धारा 9 (ए) को अधिनियमित करते हुए, 1961 के अधिनियम की धारा 51 को हटाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती, जिसमें जैसा कि ऊपर कहा गया है, विदेशी निर्णय

अधिनियम को भारत के कानून द्वारा शासित मध्यस्थता समझौतों पर किए गए किसी भी निर्णय पर लागू होने से बाहर रखा गया है।

13. इस मामले में, समवर्ती क्षेत्राधिकार के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से विदेशी निर्णय अधिनियम की धारा 9 (बी) को हटाने के साथ अनुमति दी गई थी, जबकि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग-2 को अधिनियमित किया गया था, जिसने पहले के तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया था और मध्यस्थता के कानून को एक क़ानून में डाल दिया था, हालांकि चार अलग-अलग भागों में।

14. तथापि, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस. ए. एंड अनदर, (2002) 4 धारा 105 में इस न्यायालय ने समवर्ती अधिकारिता के इस सिद्धांत को अनुच्छेद 32 में यह अभिनिर्धारित करते हुए पुनर्जीवित किया कि जहां भी मध्यस्थता भारत के बाहर आयोजित की जाती है, जब तक कि पक्षकार मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग-1 के आवेदन को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर करने के लिए सहमत नहीं होते हैं, भारत में न्यायालय उस देश के न्यायालय के साथ समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग करेंगे जिसमें विदेशी निर्णय दिया गया था। भाटिया इंटरनेशनल उस मामले में प्रतिवादी द्वारा 1996 के अधिनियम के भाग-I के तहत भारतीय कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेशों के लिए की गई धारा 9 के आवेदन के संदर्भ में था, जिसके खिलाफ भारत में

एक विदेशी निर्णय निष्पादित किया जाना था। वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग बनाम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड एंड अनदर, (2008) 4 एस. सी. सी. 190 के फैसले में समवर्ती अधिकार क्षेत्र के इस सिद्धांत में कमी और बेतुकेपन को सबसे मार्मिक रूप में महसूस किया गया, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक विदेशी निर्णय को भी घरेलू निर्णय के रूप में माना जाएगा और इसलिए 1996 के अधिनियम के भाग-I की धारा 34 में प्रदान की गई चुनौती प्रक्रिया लागू होगी। इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विदेशी निर्णय को उस देश में चुनौती दी जा सकती है जिसमें इसे बनाया गया है; इसे भारत में 1996 के अधिनियम के भाग-I के तहत भी चुनौती दी जा सकती है; और 1996 के अधिनियम के भाग-II में निहित धारा 48 के तहत मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है।

15. कानून की इस स्थिति को देखते हुए, भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज, इंक., (2012) 9 एस. सी. सी. मामले में इस अदालत की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने भाटिया इंटरनेशनल और वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग दोनों को खारिज कर दिया। लेकिन इन निर्णयों को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः "भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 एस. सी. सी. 105] में निर्णय इस न्यायालय द्वारा 13-3-2002 पर दिया गया था। तब से, उपरोक्त निर्णय का सभी उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर पालन किया

गया है। वास्तव में, वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग [(2008) 4 एससीसी 190] में निर्णय भाटिया इंटरनेशनल [(2002) 4 एससीसी 105] में निर्णय के अनुपात के संदर्भ में 10-1-2008 पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, पूर्ण न्याय करने के लिए, हम एतद्द्वारा आदेश देते हैं कि इस न्यायालय द्वारा अब घोषित कानून इसके बाद निष्पादित सभी मध्यस्थता समझौतों पर संभावित रूप से लागू होगा। [पैरा 197 पर]

16. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि वर्तमान मामले जैसे तथ्य समवर्ती अधिकार क्षेत्र के भाटिया अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को आकर्षित करते हैं क्योंकि 12.9.2012 से पहले किए गए सभी मध्यस्थता समझौते, जो कि भारत एल्यूमीनियम कंपनी के फैसले के उच्चारण की तारीख है, भाटिया इंटरनेशनल द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

17. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाटिया इंटरनेशनल के पैराग्राफ 32 में ही इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग-1 लागू नहीं होगा यदि इसे या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है। इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भाग-1 को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है यदि यह पाया जाता है कि किसी मामले के तथ्यों पर मध्यस्थता का न्यायिक स्थान भारत के बाहर है या मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाली कानून भारतीय कानून के अलावा कोई

अन्य कानून है। यह अब इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला (देखिएः वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और ए. एन. आर., (2011) 6 एस. सी. सी. 161, डोज़को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डूसन एनफ्राकोर कंपनी लिमिटेड, (2011) 6 एस. सी. सी. 179, योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम सांग योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2011) 9 एस. सी. सी. 735), इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2014) 7 एस. सी. सी. 603, और हार्मनी इनोवेशन शिपिंग लिमिटेड बनाम गुप्ता कोल इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर., (101 मार्च, 2015 को 2015 की सिविल अपील संख्या 610 में निर्णय लिया गया) द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

18. वास्तव में, सद्भाव के मामले में, इस न्यायालय ने उपरोक्त सभी निर्णयों को निर्धारित करने के बाद, उस मामले में अनुच्छेद 32 में मध्यस्थता खंड को निम्नानुसार निर्धारित कियाः "इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, हमें समझौते में खंडों की अवधि को विशेष रूप से स्कैन करने की आवश्यकता है; उचित परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता खंड। उक्त खंड इस प्रकार हैः "5. यदि इस चार्टर के तहत कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होना चाहिए, तो लंदन में लागू होने के लिए सामान्य औसत/मध्यस्थता, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाना है, तीसरा इस प्रकार चुने गए दोनों द्वारा, और उनका निर्णय या उनमें से

किसी दो का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और इस समझौते को लागू करने के लिए, अदालत का नियम बनाया जा सकता है। कहा कि तीन पक्ष वाणिज्यिक पुरुष हैं जो लंदन मध्यस्थ संघ के सदस्य हैं। इस अनुबंध को अंग्रेजी कानून के अनुसार नियंत्रित और समझा जाना है। उन विवादों के लिए जहां किसी भी पक्ष द्वारा दावा की गई कुल राशि 50,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं है, मध्यस्थता पृष्ठ 33 33 लंदन समुद्री मध्यस्थता संघ की छोटी दावा प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए। [पैरा 32 पर]

इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गयाः "वर्तमान मध्यस्थता खंड की शर्तों पर आते हुए, यह दिन के रूप में स्पष्ट है कि यदि चार्टर के तहत कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होंगे, तो लंदन में मध्यस्थता लागू करने के लिए; कि मध्यस्थ वाणिज्यिक पुरुष होने चाहिए जो लंदन मध्यस्थता संघ के सदस्य हैं; अनुबंध को अंग्रेजी कानून द्वारा समझा और नियंत्रित किया जाना है; और यह कि यदि दावा कम राशि के लिए है, तो लंदन समुद्री मध्यस्थता संघ की छोटी दावा प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता का संचालन किया जाना चाहिए। समझौते में कोई अन्य प्रावधान नहीं है कि कोई अन्य कानून मध्यस्थता खंड को नियंत्रित करेगा। [पैरा 41 में]

इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर प्रश्नगत खंड की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट है कि इच्छित प्रभाव लंदन में मध्यस्थता का स्थान

होना है। वाणिज्यिक पृष्ठभूमि, अनुबंध का संदर्भ और पक्षों की परिस्थितियाँ और जिस पृष्ठभूमि में अनुबंध किया गया था, वह उस दिशा में अप्रत्याशित रूप से नेतृत्व करता है। हम इस निवेदन से प्रभावित नहीं हैं कि इस तरह की व्याख्या से यह प्रतिवादी को एक लाभप्रद स्थिति में डाल देगा। इसलिए, हम समझते हैं कि इस खंड की व्याख्या करना उचित होगा कि यह एक उचित खंड या सारभूत खंड है न कि एक संक्षिप्त या प्रक्रियात्मक आदेश जिसके द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही की जानी है और इसलिए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि मध्यस्थता का स्थान लंदन में होगा।

यह कहने के बाद कि भाटिया इंटरनेशनल (उपरोक्त) में कहा गया निहित बहिष्करण सिद्धांत लागू होगा, समझौते के खंड को ध्यान में रखते हुए, परिशिष्ट से संबंधित उठाए गए विवाद पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त दस्तावेज़ पर रखी गई किसी भी व्याख्या से उस अंतिम निष्कर्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस पर हम पहले ही पहुँच चुके हैं। [पैरा 46 और 47 पर]

19. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भले ही मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाले कानून को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, फिर भी इस न्यायालय ने विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मध्यस्थता का स्थान लंदन होगा और इसलिए, आवश्यक निहितार्थ से, भाटिया अंतर्राष्ट्रीय का अनुपात लागू नहीं होगा।

20. भारत एल्यूमीनियम के फैसले के अंतिम पैराग्राफ को अब दो चेतावनियों के साथ पढ़ा जाना है, दोनों ही भाटिया इंटरनेशनल के पैराग्राफ 32 से निकलते हैं-कि जहां अदालत इस निर्धारण पर आती है कि न्यायिक स्थान भारत के बाहर है या जहां भारतीय कानून के अलावा अन्य कानून मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करता है, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग-1 को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा जाएगा। इसलिए, भाटिया सिद्धांत द्वारा शासित मामलों में भी, यह केवल वे मामले हैं जिनमें समझौते यह निर्धारित करते हैं कि मध्यस्थता का स्थान भारत में है या जिनके तथ्यों पर मध्यस्थता के स्थान पर भारत के बाहर होने के कारण निर्णय नहीं लिया जा सकता है जो भाटिया सिद्धांत द्वारा शासित होते रहेंगे। इसके अलावा, यह केवल वे समझौते हैं जो यह निर्धारित करते हैं या पढ़ा जा सकता है कि मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करने वाला कानून भारतीय कानून है जो भाटिया शासन द्वारा शासित होता रहेगा।

21. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय पहले ही दोनों को निर्धारित कर चुका है कि मध्यस्थता का न्यायिक स्थान लंदन में है और मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी कानून द्वारा शासित है। यह मामला होने के कारण, भारत संघ के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग-1 लागू होगा। भाग-I के तहत किया गया धारा 14 का आवेदन परिणामस्वरूप बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि श्री रंजीत कुमार द्वारा दो बार हल किए गए प्रश्न को फिर से खोलने का बहादुर प्रयास, यानी हमारे सामने आग्रह किए गए आधार पर एक समीक्षा याचिका और एक उपचारात्मक याचिका दोनों को खारिज करके, उसी का सामना करना चाहिए। मथुरा प्रसाद बाजु जयसवाल बनाम दोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय, (1970) 1 एस. सी. सी. 613 के मामले का हवाला देते हुए उनका तर्क, कि न्यायपालिका अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों से नहीं जुड़ेगी, वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि पी. एस. सी. के खंड 34.2 का प्रभाव तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न उठाता है, न कि तथ्यों से असंबंधित अधिकार क्षेत्र का एक शुद्ध प्रश्न। इसलिए, दोनों न्यायिक आधारों के साथ-साथ दिनांकित 28.5.2014 निर्णय में निर्धारित कानून के आधार पर, धारा 14 के तहत यह आवेदन खारिज होने योग्य है। यह न्यायालय की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है जैसा कि डॉ. सिंघवी ने सही तर्क दिया है। यह केवल UNCITRAL मध्यस्थता नियमों के तहत आगे बढ़ने और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय दिनांक 10.06.2013 से एक प्रतिकूल निर्णय प्राप्त करने के बाद है कि वर्तमान आवेदन दो दिन बाद अर्थात् 12.6.2013 पर मध्यस्थता अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर किया गया था। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय सही है और इसके परिणामस्वरूप इस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।